प्रदेश को केंद्र से मिलेगी 264 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि

धामी के नेतृत्व वाले गुड गवर्नेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने फिर सराहा

देहरादून। शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर से लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। ये विभाग सीएम धामी के पास ही हैं।

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए कहा था। इन सुधारों को लागू करने के क्रम में मंत्रालय ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के क्रम में कुल 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इसमें शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित

हम केंद्र के सभी दिशा निर्देशों को पूरी निष्ठा के साथ अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आवास और शहरी विकास विभाग में किए गए रिफार्म पर 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस का एक आदर्श मॉडल बनकर सामने आया है। - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रेनेज कार्य) के लिए तीन करोड़, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ और निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अधीन लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है। अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफार्म के तहत उत्तराखंड आवास विभाग ने टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किए थे, जिसके लिए मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग के मानक लागू करने के लिए पांच करोड़ स्वीकृत किए हैं। सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि आवास विभाग सीएम धामी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों मे शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। ब्यूरो